an>

Title: Need to provide proper minimum support price to the farmers in order to stop exploitation.

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) : अध्यक्ष महोदया, देश में धान उत्पन्न करने वाले राज्यों में किसानों को धान का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान आर्थिक रूप से टूट गये हैं। धान की लागत अधिक आती है लेकिन धान का मूल्य किसानों को लागत के बराबर भी नहीं मिला है। यहां तक कि सरकार जो किसानों की फसलों का मूल्य निर्धारण करती है, वह भी किसानों को नहीं मिल पाया है। प्रारंभ में, धान 1150 रुपये और 1250 रुपये प्रति क्वींटल बिक चुका है। अभी किसान पुरानी प्राकृतिक आपदा की भरपाई नहीं कर पाये थे कि धान की कीमत कम होने के कारण वे और ज्यादा टूट गये हैं। अब समय आ गया है कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से संपर्क करके किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना चाहिए। किसान बहुत रोष में हैं और इस दिशा में सोचने लगे हैं कि जब उद्योगपतियों को अपने उत्पाद का खुद लाभकारी मूल्य निर्धारण करने का अधिकार है तो किसानों को यह अधिकार क्यों नहीं है? किसानों को उनकी फसल का मूल्य निर्धारण करने में बिचौलियों के हाथ में शोषण के लिए छोड़ दिया जाता है। वे अपने अनुसार प्रतिदिन मूल्य का निर्धारण करते हैं। साथ ही, वे किसानों से सस्ते मूल्य पर उनके उत्पादों को खरीद कर जमाखोरों को फायदा पहुंचाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, अब समय है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से वार्ता कर किसानों के आर्थिक शोषण पर अंकुश लगाये और आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारों से मिलकर किसानों पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए कोई नयी नीति बनाये।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री देवजी एम. पटेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री राजीव सातव और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : मान्यवर, आज आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका अधिकार से नम्बर आया है।

â€¦(व्यवधान)